



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को एक निजी होटल में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

‘राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 65 % से अधिक वृद्धि की है’

मु.मंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि, राज्य सरकार ने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को व अडोबी जैसी कम्पनियों से साझेदारी की है। इससे बड़ी संख्या में इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल रहा है

जयपुर, 13 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

शर्मा मुम्बई में एक निजी होटल में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जैनपैक्ट के गठन के 20 वर्ष पूरे होने की बधाई देते हुए कहा कि जयपुर और जोधपुर में जैनपैक्ट में कार्यरत लगभग 8 हजार लोगों में 90

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को एक निजी होटल में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित किया और जैनपैक्ट के गठन के 20 साल पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि जयपुर और जोधपुर में जैनपैक्ट में कार्यरत 8 हजार लोगों में से 90 प्रतिशत स्थानीय हैं।

प्रतिशत से अधिक काम करने वाले स्थानीय हैं। यह पूरा इको-सिस्टम राज्य में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में भी जैनपैक्ट ने निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरतल पर उतारने के लिए पूरा सहयोग कर रही है।

रा. है। जैनपैक्ट के सीईओ बी.के. कालरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में निवेश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट से निवेशकों के लिए राज्य में निवेश की गई राह खुली है। उन्होंने कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैनपैक्ट वर्तमान में राज्य में हजारों युवाओं को रोजगार दे रही है तथा आगे भी प्रदेश के विकास में वे अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएंगे।

इस अवसर पर जैनपैक्ट के कंन्टी हैड पीयूष मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल सहित अधिकारियों, जैनपैक्ट कंपनी के अधिकारी एवं देश-विदेश से आए प्रतिभागी उपस्थित रहे।

जाने-माने चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नहीं, बल्कि उनकी कंपनी आईपैक के जरिए किशोर ने पिछली बार किशोर ने द्रमुक के लिए काम किया था।

इस आधार पर राजनैतिक विश्लेषक विजय और अन्नद्रमुक के करीब आने की संभावना से इंकार नहीं कर रहे हैं। दोनों अपने वोटों को एकजुट कर सकते हैं। इससे द्रमुक की चिंताएं बढ़ सकती हैं।

सवाल यह है कि क्या एक्टर विजय और अन्नद्रमुक (ई. पत्तनीस्वामी गुट) के बीच चुनावी समझौता हो सकता है? राजनैतिक विश्लेषक हैरान हैं कि क्या प्रशांत किशोर दोनों को करीब लाकर आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व दोनों के बीच चुनावी पंच बैठक बनकर चला सकते हैं? राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

एक्टर विजय एक महीने से जनसंपर्क अभियान पर सड़कों पर घूम रहे हैं। सुत्रों ने कहा कि अप्रैल में विजय तमिलनाडु का तूरुफान दौरा करेंगे। युवा वर्ग को साधक विजय तमिलनाडु की राजनीति में विपक्ष की जगह लेना चाहते हैं और अन्नद्रमुक अपने खोए जनाधार को पुनः पाने के लिए काम कर रही है। भाजपा भी अपना जनाधार बढ़ा रही है। अगर ये तीनों अलग-अलग दिशा में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से द्रमुक को लाभ होगा और द्रमुक नहीं चाहती कि विपक्षी ताकतों का पुनर्गठन हो।

पर, अभी तो शुरुआत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि विजय और उनकी पार्टी अकेले लड़े तो विपक्ष के वोट बंटेंगे और द्रमुक को लाभ होगा।

समरावता में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता राजेश गोस्वामी ने अदालत को बताया कि इस मामले में चार एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों ने उप चुनावों का बहिष्कार किया था और वे शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ही उन पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारों व पुलिस अफसरों की ओर से दफाब बनाया गया और निर्दोष ग्रामीणों पर स्थानीय प्रशासन व पुलिस ने चरम फैसा। मामले में कोई कार्रवाई करने की बजाय पुलिस से उनके खिलाफ ही झूठी एफआईआर दर्ज कर ली। याचिका में कहा गया कि, प्रकरण में पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। इसलिए मामले की हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच कराई जाए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की केस डायरी तलब की है।

‘20 माह पहले ही लगा देते राष्ट्रपति शासन तो इतना नुकसान नहीं होता’

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन यदि 20 माह पहले ही लगा दिया होता तो वहां नागरिक हिंसा में मारे नहीं जाते और हजारों लोगों को विस्थापित नहीं होना पड़ता। पार्टी ने कहा है कि मणिपुर में आखिरकार वही हुआ जिसकी मांग कांग्रेस पिछले 20 माह से कर रही है, अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मणिपुर में राष्ट्रपति

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस ने कहा।

शासन लगाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में संविधानिक तंत्र के पूर्ण रूप से ठप्प हो जाने की बात कही, जिसके चलते 03 मई 2023 से अब तक 300 से अधिक लोगों की हत्या और 60,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का विस्थापन हुआ। यह तब हुआ है जब मणिपुर के सामाजिक ताने-बाने को गंभीर रूप से क्षति पहुंचने दी गई। यह तब हुआ है जब फरवरी 2022 में भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत मिला लेकिन उनकी राजनीति ने महज पंद्रह महीनों के भीतर इस भयानक त्रासदी को जन्म दिया।

उन्होंने कहा यह तब हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति संभालने में पूरी तरह से विफल रहे जबकि इस दायित्व को प्रधानमंत्री ने उन्हें सौंपा था और यह तब हुआ है जब दुनिया भर में घूमने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर जाने और वहां सुलह प्रक्रिया शुरू करने से लगातार इन्कार करते रहे।

कृषि उपज...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उक्त कार्यों पर स्वीकृत लागभ 24 करोड़ रुपये की राशि से कृषि उपज मण्डी समितियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा, जिससे व्यापारियों एवं किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सम्पर्क सड़कों के निर्माण से किसानों एवं आमजन की मण्डी समिति तक पहुंच सुगम होगी। साथ ही, किसानों को कृषि जिनसों के विक्रय करने में समय एवं ईंधन की बचत भी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने “अवैध पत्नी” व “रखैल” जैसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए बाँम्बे हाईकोर्ट को फटकार लगाई

नई दिल्ली, 12 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाँम्बे हाईकोर्ट को फटकार लगाई। तलाक के मामले में हाईकोर्ट ने महिला के लिए “नाजायज पत्नी” और “वफादार शाधिका” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। शीर्ष अदालत ने इसे महिला विरोधी बताया हुआ कि ऐसी भाषा न केवल संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भी है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने बाँम्बे हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग पूरी तरह अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि किसी महिला का विवाह अमान्य घोषित किया जाना एक कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे “अवैध पत्नी”

नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय नया इनकम टैक्स बिल लाने की घोषणा की थी

नई दिल्ली, 13 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश कर दिया। यह बिल पुराने आयकर कानून से काफी अलग है। इस बिल के तहत टैक्स फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को खासतौर पर कम करने की कोशिश की गई है। निर्मला सीतारमण ने सदन में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि नए बिल के तहत शब्दों की संख्या घटाई गई है। लोकसभा में पेश किए गए इस नए बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पहले से सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। जातव्य है कि बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय इस बात का ऐलान किया था कि केंद्र सरकार नया आयकर बिल लेकर आ रही है।

नए टैक्स नियमों का बिल के पारित होने के बाद कई नए शब्दों का चलन बढ़ जाएगा। जैसे पहले फाइनेंशियल इंयर, प्रीवियस इंयर, असेसमेंट इंयर और ऐसे ही कई शब्दों का इस्तेमाल

नए बिल में कर प्रणाली का सरलीकरण करने पर जोर दिया गया है।

नए बिल में 536 सैक्शन, 16 अनुसूचियां व 23 चैप्टर्स हैं।

किया जाता था। वहां अब इनकी जगह टैक्स इंयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे टैक्सपेयर्स को समझने में आसानी होगी। नए बिल के तहत छूट से लेकर नए नियमों को अलग-अलग सैक्शन में विस्तार से बताया गया है। नए बिल के तहत कुल 536 सैक्शन, 16 अनुसूचियां और कुल 23 चैप्टर्स हैं। मौजूदा कानून में कुल 14 अनुसूचियां हैं लेकिन अब नए बिल में इसकी संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है।

सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 से तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है। यानी यह साफ है कि नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। नए कानून के तहत टोटल इनकम

अमेरिका में भारी समर्थन... भारत को यकीन है,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तुलना में गैर-सहयोगी राज्यों और शहरों की संयोगी निधि रोकने के पक्ष में ज्यादा रुझान दर्शाया है। जातीय या नस्लीय पृष्ठभूमि को अनदेखा कर दें तो डेमोक्रेट्स टम्प की आप्रवासन नीतियों का भारी विरोध करते हैं। हालांकि, एशियाई (43 प्रतिशत) और अरबत (40 प्रतिशत) डेमोक्रेट्स प्रशासन के निर्वासन प्रयासों का समर्थन करते हैं, जबकि श्वेत (32 प्रतिशत) और हिस्पैनिक (27 प्रतिशत) डेमोक्रेट्स कम समर्थन दिखाते हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक विचारों का जातीय और नस्लीय समूहों के भीतर भी गहरा प्रभाव है, जो अमेरिका में आप्रवासन मुद्दों पर गहरे धुवीकरण को उजागर करता है।

जनाती की टुंग की आप्रवासन नीतियों पर राय राजनीतिक रुझान के अनुसार काफी भिन्न है। रिपब्लिकन और रिपब्लिकन-शुकाव वाले स्वतंत्र लोगों में 74 प्रतिशत लोग महसूस करते हैं कि प्रशासन निर्वासन के मामले में उचित कदम उठा रहा है, जबकि केवल 12 प्रतिशत को लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है और 13 प्रतिशत का मानना है कि यह अत्यधिक है। इसके विपरीत, 73 प्रतिशत डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स-शुकाव वाले स्वतंत्र लोग मानते हैं कि प्रशासन निर्वासन के मामले में बहुत अधिक कर रहा है। केवल 21 प्रतिशत डेमोक्रेट्स को लगता है कि प्रयास पर्याप्त है, जबकि केवल 4 प्रतिशत मानते हैं कि प्रशासन पर्याप्त नहीं कर रहा है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक समझौते में एक नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डी.सी., अमेरिका की आधिकारिक कामकाजी यात्रा पर पहुंचे।

यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकी कैबिनेट के सदस्यों और उद्योग जागत के नेताओं से मिलेंगे।

पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के किंग अबदुल्ला के बाद उनसे मिलने वाले चौथे विदेशी नेता होंगे।

मोदी ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे। बुधवार शाम को प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने पर ब्लेयर हाउस के पास बड़ी संख्या में एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश

लोकसभा में जेपीसी प्रमुख जगदंबिका पाल और राज्यसभा में सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की

नई दिल्ली, 12 फरवरी। बजट से पहले चरण का आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने और लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। हालांकि, इसके बाद ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि समिति ने उनकी बात नहीं सुनी। तब इस विषय पर फिर से हंगामा हुआ।

राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्षी दलों के भारी हंगामा शुरू कर दिया। सुबह सदन की कार्यवाही

इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

आरंभ होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे सांसद आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे।

हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन में व्यवस्था बनाने की अपील की। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी।

धनखड़ ने कहा कि भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का संदेश है यह और इसे सदन में पेश न होने देना उनका अपमान होगा। धनखड़ ने हंगामा कर रहे सांसदों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

गौतम अडानी ने श्रीलंका के एक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है, जिन्हें अडानी समूह ने भारतीय सरकार के कूटनीतिक दबाव के तहत प्राप्त किया था।

कंपनी को दो परियोजनाओं में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कुल 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना था और इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी थीं। अनुरा कुमारा प्रशासन अब इस परियोजना की समीक्षा कर रहा है। क्योंकि नए राष्ट्रपति बिजली की लागत को घटाना चाहते हैं। अदानी प्रीन एनर्जी लि. (ए.जी.ई.एल.) ने कहा, “हालांकि, हम श्रीलंका के प्रति प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में सहयोग के लिए तैयार हैं, यदि श्रीलंका सरकार चाहती है तो।”

तथापि, कोलंबो में, श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह प्रोजेक्ट में अडानी समूह अभी भी काम कर रहा है, जिसमें उसका 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैसा लगा हुआ है।

अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाना था। यह परियोजना, जो 2026 के मध्य तक पूरी होने वाली थी, को पर्यावरणीय समूहों के विरोध के अलावा श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में इकोलॉजिकल चिंताओं पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

पिछले साल मई में, श्रीलंका की पूर्व सरकार ने प्रस्तावित अडानी पवन संयंत्र से 0.0826 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा की रेट से बिजली खरीदने पर सहमति दी थी।

तथापि, नई सरकार ने अडानी समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ अमेरिकी अदालत में आरोप लगाने के बाद अनुबंध की जांच शुरू कर दी थी। अडानी समूह पर आरोप था कि भारत में रिन्युएबल एनर्जी सप्लाई का अनुबंध प्राप्त करने के लिए उसने भारत में अधिकारियों को रिश्वत दी है।

मांग को पूरा करने में असमर्थ, अडानी समूह प्रोजेक्ट से पीछे हट गया है।

समूह ने 12 फरवरी को यह कहते हुए श्रीलंकाई सरकार को अपना निर्णय सूचित किया, कि उसे यह जानकारी मिली है कि परियोजना के प्रस्ताव पर पुनः बातचीत के लिए कैबिनेट द्वारा नियुक्त दो समितियाँ गठित की जाएंगी। ए.ई.जी.एल. के बोर्ड ने इस मुद्दे पर विचार किया और निर्णय लिया कि, कंपनी श्रीलंका के संप्रभु अधिकारों और उसके विकल्पों का पूरी तरह से सम्मान करती है, तथापि, वह इस परियोजना से सम्मानपूर्वक पीछे हट गया है।

मणिपुर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हिंसा की घटनाओं के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी। राज्य में हिंसा में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का मानना है कि “ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती।”

‘आर.पी.एस.सी. के अफसरों के पेपर लीक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) याचिकाकर्ताओं द्वारा तब भी अदालत में नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद 16 दिसम्बर 2023 को ही सरकार ने घोषणा की थी कि पिछली गहलोत सरकार में आयोजित परीक्षाओं की जांच के लिए निष्पक्षता के लिए राज्य सरकार ने एस.आई.टी. का गठन किया और फरवरी-मार्च 2024 में मामले में पहली एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि अधिकारताओं ने अदालत को कहा कि याचिकाकर्ताओं ने लगभग डेढ़ साल तक कोई याचिका दायर नहीं की और जिस दिन (13 अगस्त 2024) एस.ओ.जी. की रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी गई। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी तथ्य छुपाये कि वह सभी परीक्षा में अभ्यर्थी थे और पुलिस और एस.ओ.जी में भी कर्मचारियों के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने यह तथ्य बताकर यह बताते की

कोशिश की कि याचिकाकर्ता अवांछित कारणों से प्रेरित होकर याचिका दायर कर रहे हैं और इनमें से कई याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा के परिणामों को रद्द करने की गुहार नहीं की है, क्योंकि वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण थे और वह स्वयं लाभाभी रहेंगे अगर साक्षात्कार में कई उच्च रैंक वाले अभ्यर्थियों को हटा दिया जाये। हालांकि, सभी याचिकाकर्ताओं ने दस मई भर्ती परीक्षा-2022 को पूरित: रद्द करने की गुहार की है।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पहले दिन से ही राज्य सरकार ने मामले की जांच शुरू करने के लिये एस.आई.टी. गठित कर दी थी और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच करवा रही है, परंतु जांच में हुए तथ्य सामने आना कि आर.पी.एस.सी. के अफसर भी पेपरलीक में शामिल हो सकते हैं या नहीं, से मामला जटिल हो गया है क्योंकि आर.पी.एस.सी. के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराई गई जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह का कहना था कि अगर राज्य सरकार तुरंत ही परीक्षा निरस्त करती है तो गिरफ्तार किये गये अफसरों की देखरेख में आर.पी.एस.सी.द्वारा आयोजित

परीक्षाओं पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जायेगा और फिर सरकार को उन सभी परीक्षाओं की भी निरस्त करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के समक्ष रिट पिटिशन 13 अगस्त 2024 को दायर की गई थी लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त को हुआ था। तथ्यों के अनुसार, 31 अगस्त को अधिकारी रामू राम रायका की पुत्री और बेटे को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था फिर 1 सितम्बर का रामूराम रायका की गिरफ्तार किया गया था। फिर 2 सितम्बर को आर.पी.एस.सी. अफसर बाबू लाल कटारा को भी गिरफ्तार किया गया था। यहां गौर फरमाने योग्य है कि दोनों गिरफ्तारियों के बाद भी महाधिवक्ता ने 5 सितम्बर 2024 को गृह विभाग को अपनी विधिक सलाह दी थी कि परीक्षा को रद्द किया जा सकता है जो गृह विभाग को 14 सितम्बर को मिली थी।

मामले से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि महाधिवक्ता के समक्ष इस मामले की जांच और कानूनी जटिलताओं की संपूर्ण पृष्ठभूमि स्पष्ट थी और इसके बावजूद उन्होंने परीक्षाओं को रद्द करने की सलाह दी। इन अधिवक्ताओं का कहना था कि परीक्षा को रद्द करने और उसे आर.पी.एस.सी.

ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 3 की मौत

भिंड, 13 फरवरी। मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लहार अनुविभाग के बरहा गांव के नजदीक बीहड़ में एक पुल पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली फट गयी। दुर्घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गयी और एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए दतिया जिले के सेवड़ा।

हादसा मध्यप्रदेश के भिंड जिले के बरहा गांव के पास हुआ। इसमें तीन महिलाओं की मौत हो गई व एक दर्जन लोग घायल हो गए।

अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है।

पुलिस सुत्रों के अनुसार दतिया जिले के मगरली गांव से ट्रैक्टर पर सवार होकर 30 से 40 लोग रफ्तार में एक शादी समारोह में भिंड जिले के लहार आ रहे थे जो सभी लड़की पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं।

के अफसरों को हटाने के साथ क्यों उलझाया जा रहा है। राज्य सरकार के यह रुख अपनाने से हाई कोर्ट के गलतियों में और आमजन में भी यह आशंका फैल रही है कि याचिका खारिज करते ही सरकार जांच और गिरफ्तारियों के सिलसिले में हिलाई लायेगी। उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार के दौरान रीट पेपर लीक को लेकर अदालत ने याचिका दायर की गई थी। अदालत में अपनी देखरेख में इसकी जांच एस.डी.जी. के अफसर अशोक राठौड़ को सौंपी थी।

सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के लिफ्ट होने का भी जिक्र किया गया था। हालांकि अंत में अदालत ने ए.डी.जी. अशोक राठौड़ की जांच को संपूर्ण मानते हुए याचिका इस आदेश के साथ खारिज कर दी थी कि मामले की जांच जारी रहेगी और सभी अपराधियों की गिरफ्तार किया जायेगा। परन्तु, याचिकाओं के बाद किसी भी बड़े आशंका या नेता की गिरफ्तारी नहीं की गई। और न ही पेपर लीक के रसनाओं को पकड़ा गया। वर्तमान में भी यह चर्चा होना कि याचिकाओं के खारिज करने के बाद किसी भी बड़े अफसर की गिरफ्तारी नहीं होगी।